

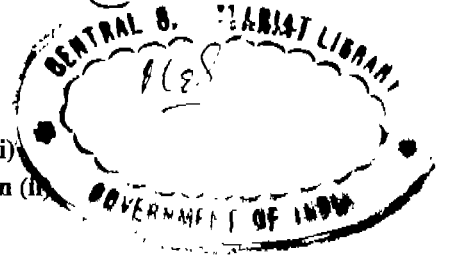


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 353]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 29, 2001/ज्येष्ठ 8, 1923

No. 353]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 29, 2001/JYAISTHA 8, 1923

पोत परिवहन मंत्रालय

(श्रम प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2001

का. आ. 477 (अ).—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के उपबंध के अनुसार मद्रास गोदी कामगार बोर्ड, इसके कामगारों और चेन्नै पोर्टन न्यास के प्रबंधन के बीच एक समझौता हुआ है;

अतः अब केन्द्र सरकार, गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन), (महापत्तनों के अप्रयोज्यता) अधिनियम, 1997 (1997 का 31) की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निर्देश देती है कि गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के उपबंध दिनांक 28 मई, 2001 से चेन्नै पोर्टन के संबंध में लागू नहीं रहेंगे।

[फा. सं. एलबी-13022/1/2001-एल. IV]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(LABOUR DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2001

S.O. 477(E).—Whereas a settlement has been arrived at between the Madras Dock Labour Board, its workmen and management of the Chennai Port Trust in accordance with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3, read with section 4, of the Dock Worker's (Regulation of Employment), (Inapplicability to Major Ports) Act, 1997 (31 of 1997), the Central Government hereby direct that the provisions of the Dock Worker's (Regulation of Employment), Act, 1948 (9 of 1948) shall cease to have effect in relation to the Port of Chennai with effect from 28th day of May, 2001.

[F.No. LB-13022/1/2001-L.IV]

K. V. RAO, Jt. Secy.

